

प्रेषक,

डी०एस० गब्यारल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

**विषय:-** मैसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इन्डस्ट्रीज लि० नई दिल्ली को ग्राम समाज की कुल 1.568 है० भूमि में से ग्राम धाथौला, परगना मंगलौर, तहसील रुड़की में 0.9540 है० भूमि सशुल्क पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-594/जी०भू०व्य०सहा०-2016 दिनांक 15.9.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम धाथौला, परगना मंगलौर, तहसील रुड़की में 0.9540 है० भूमि को शासनादेश सं०- 258/16(1)/73-राजस्व-1 दि०-09.05.1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1695/9-1-1(60)/93-280-रा०-1 दिनांक-12.09.1997 तथा शासनादेश संख्या 1115/XVII(II)/2016-18(184)/2015 दिनांक 15 जून, 2016 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्राईवेट व्यक्तियों से भूमि की कीमत वर्तमान प्रचलित बाजार दर के दो गुने निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एवं उक्त भूमि की कीमत के अतिरिक्त मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत कर धनराशि एकमुश्त जमा किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन मैसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इन्डस्ट्रीज लि० नई दिल्ली को पट्टे पर सशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।
2. प्रश्नगत जेड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि०-9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
4. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011 (एस०एल०पी०)/(सी) संख्या-3109/ 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है। उसी के लिए किया जायेगा।

6. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।
8. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
9. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।
10. भू-उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
11. संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गब्याल)  
सचिव।

पू०पू०सं० 2338 /XVIII(II)/2016-03(38)/2016 तददिनांकित  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. श्री सुभाष त्यागी, चेयरमैन मैसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इन्डस्ट्रीज लि० नई दिल्ली।
4. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(जे०पी० जोशी)  
अपर सचिव।